



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 1992/ज्येष्ठ 25, 1914

No. 370]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 1992/JYAISTHA 25, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह असाधारण के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसंचयन

नई दिल्ली, 15 जून, 1992

का. आ. 431 (अ)।—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया
निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जारीकारी के लिए प्रकाशित किया
जाता है।—

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपवंश)
प्रविनियम, 1951 (1951 का 33) के उपवंशों के अनुसरण में
राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो श्री कल्पना चन्द्र पंत,
आच्युत और निम्नलिखित बारे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्—

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. डा. देवी प्रसाद पाल, संसद सदस्य | सदस्य |
| 2. श्री ब. प. र. विठ्ठल | सदस्य |
| 3. डा. सी. रंगराजन | सदस्य |
| 4. श्री मुनीष चन्द्र गुप्त | सदस्य-सचिव |

2. अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने-अपने पद प्रदान की तारीख से
30 नवम्बर, 1993 तक पढ़ धारण करें।

3. आयोग निम्नलिखित विषय के संबंध में सिफारिश करेगा, अर्थात्—

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी अंश के आवंटन के बारे में,

(ख) भारत की संवित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान की और ऐसे राज्यों को जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से लिख प्रयोजनों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उक्त राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में संदेश राज्यों को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में।

4. आयोग सिफारिश करने में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात्—

- (i) यह उद्देश्य कि राज्यों और केन्द्र सरकार दोनों के राजस्व लेख में प्राप्ति और व्यय का संतुलन होना चाहिए और साथ ही यह भी कि पूँजी विनियोग के लिए अधिक ग्राम प्राप्त होना चाहिए तथा वित्तीय पदा कम किया जाना चाहिए;
- (ii) केन्द्रीय सरकार के साधन स्रोत क्या हैं और उनसे अवैधारणी क्या हैं; विशेषकर सिविल प्रशासन, प्रतिरक्षा और सीमा सुरक्षा, क्रष्ण सेवा पर होने वाला व्यय तथा अन्य प्रतिवध व्यय और दायित्व;
- (iii) 31 मार्च, 1995 तक पूरी की जाने वाली योजना स्कीमों का अनुरक्षण व्यय और पूँजी ग्रासिस्टियों का अनुरक्षण और रख-रखाव तथा वे प्रादेश जिनके आधार पर पूँजी ग्रासिस्टियों के अनुरक्षण के लिए विनियोग राशियों को सिफारिश की गई है, और ऐसे व्यय को मानीटर करने की रीत;
- (iv) प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए उदाहरणार्थ, भूमि अभियान का केंप्यूटरीकरण, जिला स्तर तक और उससे ऊपर सचार के त्वरित सर्व बनाना और विकास से भिन्न दोनों और सेवाओं के मानक ऊपर उठाने के लिए राज्यों की आवश्यकताएं और ऐसे व्यय को मानीटर करने की रीत;
- (v) 1993-94 में संभाव्य करावान के स्तर के आधार पर, 1 अप्रैल, 1995 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए राज्यों के राजस्व स्रोत, योजना के लिए अतिरिक्त साधन स्रोत जटाने का लक्ष्य और अतिरिक्त करावान की संभाव्यता;
- (vi) अतिरिक्त करावान की संभाव्यता को इष्ट में रखते हुए योजना से भिन्न व्यय पुरा करने के लिए राज्यों की आवश्यकताएं;
- (vii) राज्यों द्वारा किए गए करावान के प्रयास;
- (viii) राज्यों द्वारा सिचाई परियोजना, विद्युत परियोजना, राज्य परिवहन उपकरण, विभागीय वाणिज्यिक उपकरण, परिवहन सेक्टर उपकरण आदि में विनियोगों पर प्रुद्वित्यकृत प्रतिलाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता; और
- (ix) दक्षता और मितव्य से सुरक्षित वैहार वित्तीय प्रबंध की संभावना।

5. आयोग निम्नलिखित के विवरण की प्राप्ति करने वाले सिद्धान्तों में परिवर्तन के लिए मुझब्रह दे सकेगा—

- (क) राज्य सरकारों द्वारा पहले जो विकास कर उद्घटीत किया जाता था उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के मात्र) अधिनियम, 1957 के अधीन उद्गमीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के, किसी वित्तीय वर्ष में, गुरुगम,

(ख) रेल यात्री किराया अधिनियम, 1957 (निरसित) के अधीन कर के बदले में राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान।

6. पूर्वोक्त विभिन्न विषयों पर सिफारिश करने में आयोग उन सभी मामलों में जहां कर, शुल्क और सहायता अनुदान के न्यायगमन के अवधारण के लिए जनसंघया को एक गुणक मानना है, 1971 की जनगणना के आंकड़े अपनाएं।

7. आयोग, विपक्ति राहत निधि की विद्यमान स्थिरम का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके बारे में समुचित सिफारिश कर सकेगा।

8. आयोग, 31 मार्च, 1994 को यथा विद्यमान राज्यों की क्रष्ण स्थिति का निर्धारण कर सकेगा, और केन्द्र की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुधार के लिए ऐसे उपायों का मुकाबला दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

9. आयोग, पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 1995 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए, अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1993 तक उपलब्ध करा देगा। आयोग यह बताएगा कि यिस आधार पर उन्हें नियमित निकाले हैं और याजदार प्राप्ति और व्यवहार के प्रत्यक्ष करावान भी देगा।

ह०

जून, 15, 1992

(आर. वेक्टरामन)

भारत के राष्ट्रपति

[मेर एक 21(15)एफ सी डी/92]

श्री पी. वर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 1992

S.O. 431(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Shri Krishna Chandra Pant as the Chairman and the following four other Members, namely :—

1. Dr. Debi Prosad Pal, Member of Parliament, Member
2. Shri B. P. R. Vithal, Member
3. Dr. C. Rangarajan, Member
4. Shri M. C. Gupta, Member-Secretary

2. The Chairman and other members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto the 30th day of November, 1993.

3. The Commission shall make recommendations relating to the following matters :

- (a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be divided between them under Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
- (b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article.

4. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to :-

- (i) the objective of not only balancing the receipts and expenditure on revenue account of both the States and the Central Government, but also generating surplus for capital investment and reducing fiscal deficit;
- (ii) the resources of the Central Government and the demands thereon, in particular, on account of expenditure on civil administration, defence and border security, debt-servicing and other committed expenditure or liabilities;
- (iii) the maintenance and upkeep of capital assets and maintenance expenditure on plan schemes to be completed by 31st March, 1995 and the norms on the basis of which specified amounts are recommended for the maintenance of the capital assets and the manner of monitoring such expenditure;
- (iv) the requirements of States for modernisation of administration, e.g. computerisation of land records and providing faster channels of communication upto and above district level, and for upgrading the standards in non-developmental sectors and services and the manner in which such expenditure can be monitored;
- (v) the revenue resources of the States for the five years commencing on 1st April, 1995, on the basis of the levels of taxation likely to be reached in 1993-94, targets set for additional resource mobilisation for the Plan and the potential for raising additional taxes;
- (vi) the requirement of the States for meeting the Non-Plan revenue expenditure also keeping in view the potential for raising additional taxes;

- (vii) the tax efforts made by the States;
- (viii) the need for ensuring reasonable returns on investment by the States in irrigation projects, power projects, State Transport Undertakings, departmental commercial undertakings, public sector enterprises, etc.; and
- (ix) the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in expenditure.

5. The commission may suggest changes, if any, to be made in the principles governing the distribution of :-

- (a) the net proceeds in any financial year of the additional excise duties leviable under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, in replacement of the sales tax levied formerly by the State Governments; and
- (b) the grants to be made available to the States in lieu of the tax under the repealed Railway Passenger Fares Act, 1957.

6. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the population figures of 1971 in all cases where population is regarded as a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid.

7. The Commission may review the present scheme of Calamity Relief Fund and may make appropriate recommendations theron.

8. The Commission may make an assessment of the debt position of the States as on 31st March, 1994, and suggest such corrective measures as are deemed necessary also keeping in view the financial requirements of the Centre.

9. The Commission shall make its report available by the 30th November, 1993, on each of the matters aforesaid, covering a period of five years commencing on the 1st day of April, 1995. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the State-wise estimates of receipts and expenditure.

Sd/-

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT OF INDIA

15, 1992

[No. F. 21(15)-FCD/92]
B. P. VARMA, Addl. Secy.

